

मुकदमों का विवरण

मेसर्स लार्सन एयर कंडीशनिंग एंड रिफ्रिग्रेशन कंपनी

वी.

भारत और ओआरएस का संघ। (2023 की सिविल अपील संख्या 3798) 11 अगस्त, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय ने ब्याज को 18 प्रतिशत के चक्रवृद्धि ब्याज से घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष करने की सीमा तक मध्यस्थता निर्णय को संशोधित करने में गलती की है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 31-उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज में संशोधन-निम्नलिखित का स्वामित्व:

आयोजित किया गया: तत्काल मामले में, यह देखते हुए कि मध्यस्थता 1997 में शुरू हुई थी, यानी 1996 के अधिनियम के लागू होने के बाद, मध्यस्थ और उनके द्वारा पारित पुरस्कार, इस कानून के अधीन होगा-अधिनियम के तहत, यानी धारा 31 (7), ब्याज की वैधानिक दर स्वयं 18 प्रतिशत प्रति वर्ष पर विचार की जाती है-यह उस स्थिति में है जब अधिनिर्णय में ब्याज की दर के प्रति कोई निर्देश नहीं होता है-इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए उपार्जित और देय ब्याज पर मध्यस्थ के निर्णय में हस्तक्षेप करने का बहुत कम या कोई कारण नहीं है-पुराने अधिनियम के विपरीत, न्यायालय अधिनिर्णय को संशोधित करने के लिए शक्तिहीन है और केवल आंशिक रूप से, या पूरी तरह से, एक निर्णय को इस शर्त पर अलग कर सकता है कि शर्तों में यू/एस लिखा गया है।³⁴ 1996 के अधिनियम की साबित गई है। [पैरा 13]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 34-इसके अधीन अधिकारिता

आयोजित किया गया: न्यायालय यू/एस का सीमित और अत्यंत सीमित अधिकार क्षेत्र।³⁴ अधिनियम की धारा, न्यायालय को पेटेंट अवैधता के आधारों के बिना किसी निर्णय में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है, अर्थात्, "अवैधता मामले की जड़ तक जानी चाहिए और तुच्छ प्रकृति की नहीं हो सकती है"; और यह कि न्यायाधिकरण को "अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई मध्यस्थ अनुबंध की अवधि को उचित तरीके से समझता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि 87

पुरस्कार को इस आधार पर अलग रखा जा सकता है "-दूसरा आधार प्राकृतिक न्याय से इनकार करना होगा।[पैरा 15]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** -एस. **37**-निर्णयों की समीक्षा करने के लिए अपीलीय न्यायालय का कार्यक्षेत्र:

आयोजित किया गया:याचिका में कहा गया है,अधिनियम की धारा 37 अपीलीय न्यायालय को किसी निर्णय की समीक्षा करने के लिए संकीर्ण गुंजाइश प्रदान करती है, यदि इसे बरकरार रखा गया है, या यू/एस के तहत काफी हद तक बरकरार रखा गया है।³⁴ - यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुराने अधिनियम में एक प्रावधान था जो अदालत को एक पुरस्कार को संशोधित करने में सक्षम बनाता था-हालाँकि, 1996 के अधिनियम को लागू करते समय संसद द्वारा उस शक्ति को जानबूझकर हटा दिया गया है-इसका मतलब है कि संसदीय इरादा अदालत को किसी भी तरह से एक पुरस्कार को संशोधित करने की शक्ति को बाहर करना था। [पैरा 15]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

के. मारप्पन बनाम अधीक्षक अभियंता टीबीपीएचएलसी सर्कल अनंतपुर [2019] 5 एससीआर 152; मेसर्स रवीची एंड कंपनी बनामभारत संघ [2018] 5 एस. सी. आर. 138; अम्बिका निर्माण बनाम भारत संघ (2017) 14 एस. सी. सी. 323; शाही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। [2019] 11 एससीआर 640; सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा राज्य बनाम जी. सी. रॉय [1991] सप।3 एस. सी. आर. 417; ग्रेटर मुंबई नगर निगम और अन्न बनाम प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। [2018] 14 एससीआर 1143; ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी.केरल राज्य [2021] 4 एस. सी. आर. 137; स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ बनाम कलसी निर्माण कंपनी (2019) 8 एस. सी. सी. 726; सहयोगी बिल्डर बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण [2014] 13 एस. सी. आर. 895; सांगयोंग इंजीनियरिंग निर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच. ए. आई.) [2019] 7 एस. सी. आर. 522; दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड [2021] 5 एससीआर 984; राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत बनाम एम. हकीम [2021] 5 एस. सी. आर. 368-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील No.3798

2023.

2003 के एफ. ए. एफ. ओ. No.1227 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 17.07.2019 से।

88 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

रूप:

आर. के. सिंह, श्रीमती नीरज सिंह, कुमार गौरव, अजय चौधरी, प्रवीण पाठक, अमन रस्तोगी, संजय रस्तोगी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., ए. के. कौल, नचिकेता जोशी, भुवन मिश्रा, अक्षित प्रधान, सचिन शर्मा, सिद्धार्थ सिन्हा, शिवम सिंघानिया, एन. चामविबो जेलियांग, सूरज मिश्रा, सुश्री आकांक्षा, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्याय

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय 1 से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने कानून के एक सरल प्रश्न के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, कि क्या उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय को ब्याज को 18 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष करने की सीमा तक संशोधित करने में गलती की है।

तथ्य।

2. अपीलार्थी और भारत संघ (इसके बाद 'प्रत्यर्थी-राज्य') के बीच विवाद निविदा दिए जाने के अनुसरण में किए गए अनुबंध से उत्पन्न हुआ।कार्य के दौरान कुछ विवाद उत्पन्न हुए।

22.04.1997 पर, प्रतिवादी-राज्य ने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया, और कार्यवाही 24.10.1998 पर बंद हो गई।न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय 21.01.1999 पर प्रकाशित किया और पहले चार प्रत्यर्थीगणों को दावा संख्या 1-8 के संबंध में निर्णय पर 18 प्रतिशत लंबित राशि और भविष्य में चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

3.प्रतिवादी-राज्य ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम') की धारा 34 के तहत पुरस्कार को चुनौती दी।जिला अदालत 2 ने चुनौती को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह पुरस्कार पर अपील में नहीं बैठ सकती है और क्योंकि प्रतिवादी-राज्य कथित आधारों का कोई सबूत देने में विफल रहा है।पीड़ित, प्रतिवादी-राज्य ने 2003 में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।अंतरिम में, प्रतिवादी-राज्य ने उस समय देय '1,82,878.11 के खिलाफ' 06.06.2003 पर जिला न्यायालय, कानपुर में '10,00,000 जमा किया।

1 आदेश संख्या 1227/2003 से पहली अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2019।

2 मिस्क में जिला न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा पारित 06.03.2003 का निर्णय।1999 का मामला सं. 64/70।

मेसर्स लार्सन एयर कंडीशनिंग एंड रिफ्रिग्रेशन कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [एस. रवींद्र भट, जे.] 4. आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने दावा संख्या 6 पर निर्णय में तर्क को अस्वीकार कर दिया; इसने अभिनिर्धारित किया कि निविदा दस्तावेज जारी न करने और व्यवसाय को पंगु बनाने के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के लिए 3 लाख की राशि प्रदान नहीं की जा सकती थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्यवाही (वर्तमान मामले में) मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत थी और इसलिए दी गई ब्याज दर 18 प्रतिशत नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने के. मारप्पन बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया।

अधीक्षण अभियंता टी. बी. पी. एच. एल. सी. सर्कल अनंतपुर 3, मेसर्स रवीची एंड कंपनी बनाम भारत संघ 4 और अम्बिका निर्माण बनाम भारत संघ 5 का निर्णय लेते समय

लटकते ब्याज का यह प्रश्न; यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुबंध के तहत देय राशियों पर ब्याज देने का प्रतिबंध लटकते ब्याज के भुगतान से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने ब्याज की दर को 18 प्रतिशत (मध्यस्थ के आदेश के अनुसार) से घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया। शेष राशि अपीलार्थीगण द्वारा निर्णय की तारीख से 12 सप्ताह के बाद अर्जित ब्याज के साथ जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश दिया गया था। अन्य आधारों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी।

दलों की दलीलें

5. वर्तमान कार्यवाहियों में अपीलार्थी द्वारा दबाया गया आधार ब्याज की दर (दावा संख्या 9 में अधिनिर्णय से संबंधित) में संशोधन से संबंधित है और इस अपील का दायरा इस प्रश्न तक सीमित है।

6. अपीलार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता श्रीमती नीरज सिंह ने कहा कि उनका दावा वास्तव में 24 प्रतिशत लंबित ब्याज के लिए था और मध्यस्थ ने पहले ही इसे घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था। 1996 के अधिनियम की पूर्व-संशोधित धारा 31 (7) (बी) की ओर इशारा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने 'वैधानिक ब्याज दर' को कम करने में गलती की है; इस प्रावधान में निर्धारित किया गया है कि यदि मध्यस्थ ने दी गई राशि पर ब्याज दर के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया है, तो ऐसी राशि पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत का ब्याज लगेगा। मध्यस्थ ने मामले पर उचित रूप से विचार किया था और तदनुसार 8 दावों पर 18 प्रतिशत पूर्व विचाराधीन राशि और भविष्य के चक्रवृद्धि ब्याज को मंजूरी दी थी, जिसे जिला अदालत ने स्वीकार किया था। अधिवक्ता ने अनुबंध की सामान्य शर्तों (जी. सी. सी.) के खंड 70 की ओर भी इशारा किया, जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थ का निर्णय शून्य होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। इसलिए यह आग्रह किया गया कि कोई औचित्य नहीं था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

न्यायिक हस्तक्षेप के लिए ताकि वैधानिक ब्याज दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष किया जा सके। अधिवक्ता ने शाही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य की ओर ध्यान आकर्षित किया। 6 जिसमें इस न्यायालय ने धारा 31 (7) के आलोक में यथासंभव 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर को बरकरार रखा।

7. इसके अलावा, सचिव में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया था, सिंचाई विभाग, उड़ीसा राज्य बनाम जी. सी. रॉय 7 का तर्क है कि जब पक्षों के बीच समझौता ब्याज के अनुदान को प्रतिबंधित नहीं करता है और जहां पक्ष एक मध्यस्थ को संदर्भित विवाद में ब्याज का दावा करता है, तो मध्यस्थ के पास ब्याज लंबित देने की शक्ति होती है।

8. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) श्री विक्रमजीत बनर्जी ने तर्क दिया कि विवादित फैसले ने मामले को समग्र रूप से देखा है और ब्याज को 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया है। यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय ने ब्याज को अधिक उचित दर तक कम करने का निर्णय लेने से पहले भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के सभी पहलुओं पर विचार किया था। 9. यह दावा किया गया कि उस समय उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के अधिवक्ता भी इस बात पर सहमत थे कि ब्याज की वैधानिक दर बैंक दर से 1 या 2 प्रतिशत अधिक या कम होनी चाहिए, जो पिछले दशक में लगभग 7-8% रही है। नतीजतन, ब्याज की 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर पूरी तरह से अनुचित थी, और इसमें संशोधन की आवश्यकता थी।

10. एएसजी ने इस अदालत के कई फैसलों पर भरोसा किया: नगरपालिका

ग्रेटर मुंबई निगम और अन्न बनाम प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ओआरएस। 8 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के दायरे पर जोर देना

एक संवैधानिक न्यायालय; ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम की स्थिति

केरल 9 जिसमें अनुबंध में ब्याज की दर निर्धारित नहीं की गई थी, और न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 18 प्रतिशत को अत्यधिक माना गया था और इसलिए, इस अदालत द्वारा 8 प्रतिशत साधारण ब्याज तक कम कर दिया गया था; और इसी तरह स्नातकोत्तर संस्थान

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, चंडीगढ़ बनाम कलसी निर्माण

कंपनी 10 जिसमें इस अदालत ने ब्याज की दर को 18 प्रतिशत से कम कर दिया था

6 [2019] 11 एससीआर 640

7 [1991] सप.3 एस. सी. आर. 417 8 [2018] 14 एस. सी. आर. 1143 9 [2021] 4 एस. सी. आर. 137 10 (2019) 8 एस. सी. सी. 726 91

मेसर्स लार्सन एयर कंडीशनिंग एंड रिफ्रिग्रेशन कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [एस. रवींद्र भट, जे.]

न्यायाधिकरण द्वारा 9 प्रतिशत साधारण ब्याज पर, ब्याज की दर पर 18 प्रतिशत की सहमति होने के बावजूद, यह देखते हुए कि पुरस्कार लगभग 20 साल पहले पारित किया गया था।

विश्लेषण और निष्कर्ष

11. 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (बी) को 2016 के अधिनियम 3, डब्ल्यू. ई. एफ. 23.10.2015 द्वारा संशोधित किया गया था। पूर्व-संशोधित प्रावधान, मध्यस्थ को पुरस्कार से पहले और पुरस्कार के बाद दोनों ब्याज देने का अधिकार देता है, और यह निर्दिष्ट करता है कि प्रदान की गई राशि पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत का ब्याज होगा, जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक। पूर्व-संशोधित खंड, जैसा कि यह मध्यस्थ (21.01.1999) द्वारा पुरस्कार की तारीख पर था, निम्नानुसार पढ़ा गया:

“31. मध्यस्थता पुरस्कार का प्रपत्र और विषय-वस्तु

[...]

(7) (क) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, जहां और जहां तक एक मध्यस्थता पुरस्कार धन के भुगतान के लिए है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण उस राशि को उस राशि में शामिल कर सकता है जिसके लिए पुरस्कार ब्याज बनाया गया है, ऐसी दर पर जो वह उचित समझे, पूरी या धन के किसी भी हिस्से पर, उस तारीख के बीच की अवधि के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और जिस तारीख को पुरस्कार दिया गया है। (ख) एक मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित राशि, जब तक कि पुरस्कार अन्यथा निर्देश नहीं देता है, पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वहन करेगी।”

(जोर दिया गया) 12. शाही एंड एसोसिएट्स (उपरोक्त) मामले में यह अदालत, जिस पर अपीलार्थीगण ने भरोसा किया था, वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स के समान स्थिति से निपटती है, और पूरी तरह से लागू होती है:

“11. 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (बी) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि मध्यस्थ दी गई राशि पर ब्याज की दर के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं देता है, तो ऐसी राशि पर अधिनिर्णय की तारीख से भुगतान की तारीख तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। चूंकि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को 1996 के अधिनियम की धारा 85 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है, इसलिए राज्य संशोधन सहित मध्यस्थता अधिनियम की अनुसूची भी निरस्त कर दी गई है।

केवल 92 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

धारा 85 की उप-धारा (2) (ए) में अपवाद का प्रावधान किया गया है जहां एक कार्यवाही जो 1940 के मध्यस्थता अधिनियम के लागू होने पर शुरू हुई थी और 1996 के अधिनियम के लागू होने के बाद भी जारी रही थी, और सभी पक्ष 1940 के पुराने अधिनियम को लागू करने के लिए सहमत हुए थे। इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधान, जिसमें राज्य संशोधन, अर्थात् उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित पैरा 7-ए शामिल है, 1996 के अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू की गई कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे।

12. तत्काल मामले में, हालांकि समझौता 1996 के अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले था, कार्यवाही स्वीकार्य रूप से 27-10-1999 पर शुरू हुई और 1996 के अधिनियम के अनुसार संचालित की गई। यदि ऐसा है, तो उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित पैरा 7-ए का इस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। चूंकि मध्यस्थ द्वारा दी गई ब्याज की दर 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (बी) के अनुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश को उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम का पालन करके ब्याज की दर को कम करने में न्यायसंगत नहीं ठहराया गया था।

13. वर्तमान मामले में, यह देखते हुए कि मध्यस्थता 1997 में शुरू हुई थी, यानी 1996 के अधिनियम के लागू होने के बाद, मध्यस्थ और उनके द्वारा पारित निर्णय इस कानून के अधीन होंगे। अधिनियम के तहत, यानी धारा 31 (7) के तहत, ब्याज की वैधानिक दर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष पर विचार किया गया है। बेशक, यह उस स्थिति में है जब पुरस्कार में ब्याज की दर के प्रति कोई दिशा नहीं होती है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा उपार्जित और देय ब्याज पर मध्यस्थ के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। पुराने अधिनियम के मामले के विपरीत, न्यायालय पुरस्कार को संशोधित करने के लिए शक्तिहीन है और केवल आंशिक रूप से, या पूरी तरह से, एक पुरस्कार को इस शर्त पर अलग कर सकता है कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत उल्लिखित शर्तें साबित की गई हैं। अदालत द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश, अच्छी तरह से अवहेलना और चित्रित है [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली को देखें]।

विकास प्राधिकरण 11, सांगयोंग इंजीनियरिंग निर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 12 और दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 13]।

मेसर्स लार्सन एयर कंडीशनिंग एंड रिफ्रिग्रेशन कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [एस. रवींद्र भट, जे.]

14. कलसी निर्माण कंपनी (ऊपर) पर निर्भरता

प्रत्यर्थी-राज्य, यह देखते हुए कि इस न्यायालय ने तीन प्रासंगिक कारकों के आलोक में अपने अनुच्छेद 142 के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था-यह पुरस्कार 20 साल पहले पारित किया गया था, जो एक चिकित्सा संस्थान में बाल रोग केंद्र के निर्माण से संबंधित था, और उस मामले में पक्षों ने मामले को उनके विवेक पर छोड़ दिया था।

अदालत। इसी तरह, ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स (ऊपर) में इस अदालत ने निर्णय दिया कि चूंकि अनुबंध में विलंबित भुगतान पर ब्याज की पात्रता निर्धारित की गई थी, लेकिन लागू ब्याज की दर का कोई उल्लेख नहीं था-इसलिए न्यायाधिकरण को जी. सी. राय (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करना चाहिए था, और इसलिए, अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा दी गई ब्याज की दर को कम कर दिया। बृहन्मुंबई नगर निगम (उपरोक्त) के फैसले में निस्संदेह उच्च न्यायालय की एक उच्च न्यायालय के रूप में अंतर्निहित शक्तियों पर चर्चा की गई है, लेकिन यह विशेष रूप से अपने स्वयं के आदेशों को वापस लेने के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, और वर्तमान विवाद में बहुत कम सहायता प्रदान करता है।

15. अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालत का सीमित और अत्यधिक सीमित अधिकार क्षेत्र, अदालत को पेटेंट अवैधता के आधार के बिना, एक पुरस्कार में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, अर्थात्, "अवैधता को कानून के मूल तक जाना चाहिए।

और यह कि न्यायाधिकरण को "अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई मध्यस्थ अनुबंध की अवधि को उचित तरीके से समझता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि पुरस्कार को इस आधार पर अलग किया जा सकता है" [संदर्भ: एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर)]। दूसरे ने

आधार प्राकृतिक न्याय से इनकार होगा। अपील में, अधिनियम की धारा 37 अपीलीय न्यायालय को किसी निर्णय की समीक्षा करने के लिए संकीर्ण गुंजाइश प्रदान करती है, यदि इसे धारा 34 के तहत बरकरार रखा गया है, या काफी हद तक बरकरार रखा गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुराने अधिनियम में एक प्रावधान 14 था जिसने अदालत को एक निर्णय को संशोधित करने में सक्षम बनाया। हालाँकि, 1996 के अधिनियम को लागू करते समय संसद द्वारा उस शक्ति को जानबूझकर हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि संसद का इरादा अदालत को किसी भी तरह से पुरस्कार में संशोधन करने की शक्ति को बाहर करना था।

14 “15. पुरस्कार में संशोधन करने की अदालत की शक्ति

— न्यायालय आदेश द्वारा किसी पुरस्कार में संशोधन या सुधार कर सकता है।

— (क) जहाँ यह प्रतीत होता है कि अधिनिर्णय का एक भाग किसी ऐसे मामले पर है जो मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं है और ऐसे हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग किया जा सकता है और निर्दिष्ट मामले पर निर्णय को प्रभावित नहीं करता है; या

(बी) जहाँ पुरस्कार रूप में अपूर्ण है, या इसमें कोई स्पष्ट त्रुटि है जिसे इस तरह के निर्णय को लागू किए बिना संशोधित किया जा सकता है; या

(ग) जहाँ पुरस्कार में लिपिकीय गलती या आकस्मिक पर्ची या चूक से उत्पन्न त्रुटि हो।”

94

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

इस स्थिति को इस अदालत द्वारा परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 ई और 220 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम एम. हकीम 15 में निर्णायक रूप से दोहराया गया है:

“42. इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस प्रश्न को अब कम से कम 3 निर्णयों [मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक.] द्वारा हल किया गया है।बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, (2006) 11 एस. सी. सी. 181], [किन्नरी मलिक बनाम घनश्याम दास दमानी, (2018) 11 एस. सी. सी. 328:(2018) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 106], [दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम.इस न्यायालय की नेविगेंट टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड, (2021) 7 एस. सी. सी. 657]।अन्यथा भी, यह कहना कि न्यायिक प्रवृत्ति एक ऐसी व्याख्या के पक्ष में प्रतीत होती है जो धारा 34 में पुरस्कार को संशोधित, संशोधित या परिवर्तित करने की शक्ति को पढ़ती है, 1940 के अधिनियम में निहित पिछले कानून की अनदेखी करना होगा; साथ ही इस तथ्य को भी नजरअंदाज करना कि 1996 का अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर गैर-न्यायिक मॉडल कानून, 1985 के आधार पर अधिनियमित किया गया था, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर रेडफर्न और हंटर में बताया गया है, यह स्पष्ट करता है कि, किसी पुरस्कार के गुणों से निपटने के लिए अत्यंत सीमित आधारों पर सीमित न्यायिक हस्तक्षेप को देखते हुए, धारा 34 के तहत "सीमित उपाय" "सीमित अधिकार" के साथ समान है, अर्थात्, या तो एक पुरस्कार को अलग करना या मामले को धारा 34 में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत रिमांड करना।”

16. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय हस्तक्षेप की गारंटी देता है और इसके द्वारा अतीत, लंबित और भविष्य के ब्याज की दर में संशोधन की सीमा तक अलग रखा जाता है।18 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर, जैसा कि मध्यस्थ द्वारा 21.01.1999 (दावा

संख्या 9 में) पर दिया गया है, को बहाल कर दिया गया है।प्रत्यर्थी-राज्य को इस निर्णय की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

17. वर्तमान अपील, और लंबित आवेदन (ओं) यदि कोई हों, का उपरोक्त शर्तों में निपटान किया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान

15 [2021] 5 एससीआर 368